भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1685

उत्तर देने की तारीखः 27.1**2**.201**8**

स्कूलों को अनुदान

1685. श्री संजय राउतः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश भर के सभी 11 लाख स्कूलों में प्रत्येक वर्ष पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा खेल संबंधी सुविधाओं के लिए भी स्कूलों को सीधे अलग अनुदान प्रदान कर रही है; और**

**(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में स्कूलों के नाम के साथ उनको कितना-कितना अनुदान प्रदान किया गया**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से राज्यों की भागीदारी के साथ केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्कूल शिक्षा की एक समेकित योजना-समग्र शिक्षा आरंभ की है। इस कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की तीन पूर्व केंद्र प्रायोजित योजनाओं को समेकित किया गया है। यह प्री-स्कूल से कक्षा XII तक स्कूल शिक्षा क्षेत्र का विस्तार करने का एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें ‘स्कूल’ के प्री-स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों तक शिक्षा जारी रखने की परिकल्पना की गई है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान प्रदान करती है। केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों को सीधे कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत इंडोर और आउटडोर खेलों के लिए खेल उपकरणों हेतु पहली बार प्राथमिक स्कूल के लिए 5,000 रुपए, उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए 10,000 रुपए और माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 25,000 रुपए तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। 2018-19 में महाराष्ट्र राज्य में खेल अनुदान हेतु 40.80 लाख रुपए का आबंटन किया गया है।

योजना के अंतर्गत पढ़े भारत बढ़े भारत की गतिविधियों का अनुपूरण करने के लिए तथा सभी आयु के छात्रों में पढ़ने की आदत का समाविष्‍ट करने, पुस्‍तकों की खरीद सहित स्‍कूल पुस्‍तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत पहली बार प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी स्कूलों तक के लिए 5,000 रुपए से 20,000 रुपए तक पुस्तकालय अनुदान का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के लिए 2018-19 में पुस्तकालय अनुदान हेतु 113.49 लाख रुपए का आबंटन किया गया है।

विद्यार्थियों के प्रभावी प्रयोगात्मक प्रशिक्षण के लिए इस योजना में माध्यमिक स्कूलों के लिए एक समेकित विज्ञान प्रयोगशाला और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के लिए 4 विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में उन माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों जिनमें ऐसी सुविधा मौजूद नहीं है, में आवश्यकतानुसार व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रयोगशाला/कार्यशाला तथा एक कला/शिल्प/संस्कृति प्रयोगशाला का भी प्रावधान किया गया है।

इस योजना में गैर कार्यशील स्कूल उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए तथा अन्य आवर्ती लागतों जैसे कि खेल सामग्रियों के लिए उपभोज्य, खेल उपकरण, प्रयोगशालाओं, विद्युत प्रभारों, इंटरनेट, जल, शिक्षण सहायक उपकरणों इत्यादि पर व्यय के लिए सभी सरकारी स्कूलों को वार्षिक स्कूल समेकित अनुदान भी प्रदान किया जाता है। समेकित स्कूल अनुदान की राशि स्कूल में छात्रों की संख्या के आधार पर 25,000 रुपए से 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति स्कूल की श्रेणी में होती है।

\*\*\*\*\*\*